जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 27 संख्याः 299 प्रभात अजमेर, मंगलवार 30 मई, 2023 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

उत्तरी अमेरिका में घोड़ों के बारे में लिखी गई तमाम कहानियाँ व तथ्य बदलने वाले हैं। ''साइन्स'' नाम के जर्नल में छपे एक शोध में यह दावा किया गया है। घोड़ों के पुरावेशषों की जांच के बाद शोधकर्ताओं ने कहा कि, सोलहवीं सदी के पूर्वार्ध (1600) में ही यहाँ के मूल निवासियों ने समूचे अमेरिकन वैस्ट में घोड़ों को फैला दिया था और तब तक उनका यूरोपियन्स से कोई सम्पर्क नहीं हुआ था। ये नतीजे मूल निवासियों के मौखिक इतिहास से मेल खाते हैं, जिसमें यूरोपियन्स के आने से पहले से घोड़े के साथ इन लोगों के पारस्परिक संबंधों की बात बताई गई है। सत्रहवीं व अठाहवीं सदी की यूरोपियन पुस्तकों में दावा किया गया है कि, 1680 के पुएब्लो रिवोल्ट के बाद क्षेत्र में घोड़ों का प्रसार हुआ था। नए शोध के सहलेखक जिम्मी आर्टरबैरी, जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब, ''कमैन्ची'' के विशेषज्ञ हैं, ने कहा, ''हम हमेशा से जानते थे कि स्पैनिश लोगों के आने से पहले ही हमारा घोड़ों से सम्पर्क हो चुका था। अमेरिका में घोड़ों का उद्विकास तो 40 लाख साल पहले ही हो गया था लेकिन, फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार, दस हजार साल पहले वे लुप्त हो गए।'' शोध पत्र के अनुसार, संभवतः स्पैनिश उपनिवेशी 1519 में पहली बार घोड़ों को अमेरिका में वापस लाए। तब स्थानीय लोग ट्रेड नैटवर्क के जरिए घोड़ों को उत्तर की तरफ ले गए। यह पता लगाने के लिए कि, घोड़ों का प्रसार कब हुआ था, वैज्ञानिकों ने वैस्टर्न यू.एस. में मिले दो दर्जन से ज्यादा घोड़ों के अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग की व डी.एन.ए. का विश्लेषण किया, जिसमें सामने आया कि, वायोमिंग, कैन्सस और न्यूमैक्सिको में मिले घोड़ों के अवशेष पुएब्लो रिवोल्ट से भी पुराने हैं। शोध की सहलेखक ईवैट कॉलिन्स ने कहा, नतीजों से यह भी पता चलता है कि, इतिहास को समझने में स्थानीय मौखिक परम्पराओं का महत्व कितना ज्यादा है। उन्होंने कहा, इतने वर्षों तक हमारी संस्कृति को गलत तरीके से बताया जाता रहा है।

'दोनों नेताओं ने फैसला हाई कमान पर छोड़ा'

सोमवार की शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर आयोजित बैठक, जिसमें राहुल गांधी, वेणु गोपाल, रंधावा व गहलोत थे तथा पायलट बाद में शरीक हुए, में यह सारांश निकला

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मई। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नज़र आए, तथा के.सी. वेणुगोपाल ने घोषणा की कि दोनों मिलकर राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसके तौर तरीके वे प्रक्रिया पर नेतृत्व फैसला करेगा।

आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर एक मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, रंधावा, अशोक गहलोत उपस्थित थे। बाद में इसमें सचिन पायलट भी शामिल हो गए।

सूत्रों ने बताया कि सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया।

पता चला है कि पायलट ने इस प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ सहमति दे दी है कि वसुंधरा राजे और उनके भ्रष्टाचार के कारनामों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि गहलोत इस शर्त पर सहमत होंगे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- वेणु गोपाल ने बैठक के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी गहलोत व पायलट की उपस्थिति में दी।
- विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैठक में यह प्रस्ताव आया था कि, पायलट को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जायेगा।
- पायलट ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी, पर शर्त लगायी कि, वसुंधरा राजे व उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के आदेश होने चाहिये।
- ऐसा नहीं लगता कि, गहलोत इस शर्त को स्वीकार करेंगे, पर इसकी क्रियान्विति कैसे होगी इसका निर्णय हाई कमान करेगा।
- सोमवार की रात को राहुल गांधी अमेरिका के लिये प्रस्थान कर रहे हैं, अतः अभी स्पष्ट नहीं है कि, क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण, तुरंत हो जायेगा।
- ऐसा लगता है कि, पायलट को अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का मौका दिया गया है, दोनों नेताओं को राजनीतिक निर्णय में बराबर का भागीदार बनाया गया है तथा केवल गहलोत को ''फ्री हैण्ड'' नहीं मिलेगा, जैसा वे चाहते हैं।

तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ संसद के चुनाव कराने पर मंथन शुरू?

मोदी-शाह द्वय इस रणनीति के लाभ-हानि पर गंभीर मंथन कर रहे हैं?

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। पुराने जमाने से चली आ रही जाँची-परखी रणनीति रही है कि जब दुश्मन झपकी ले रहा हो या असावधान हो, उस समय उस पर एकाएक हमला बोल दो। मोदी सरकार इस रणनीति से चिंतन करती तथा अपने राजनैतिक विरोधियों को जरा सी गलती करते दबोचने पर विचार करती प्रतीत हो रही है।

भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, यह तय करने की कवायद में गंभीरता से लगा हुआ है कि अगर अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव कुछ समय पहले करा लिये जायें तथा उन्हें लाभ होगा या हानि। भाजपा का उद्देश्य विपक्ष को संगठित करने के विपक्षी दलों के प्रयासों का कमजोर करना, बल्कि उन्हें ध्वस्त करना है।

एक शीर्षस्थ सूत्र ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि आम चुनावों का छः महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनावों के साथ कराने के फायदे-नुकसान के अध्ययन की शुरूआत इसी महीने हुये कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त हार के तुरंत बाद शुरू हो गई थी।

सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव समय पूर्व कराने का विचार पैदा होने का असली कारण यह तथ्य रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जबरदस्त प्रयासों, जिनमें उनके द्वारा 19 जन सभाएं संबोधित करना तथा 6 रोड शो करना भी शामिल है, के बावजूद भाजपा की जबरदस्त हार हुई थी। संक्षेप में, भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। चुनावों की घोषणा होने के बाद, भगवा पार्टी ने पूरे राज्य में प्रचार करते हुए आठ रैलियाँ की थीं। भाजपा के स्वयं के आंकड़े बताते हैं कि पार्टी नेता राज्य के 311 मंदिरों और मठों में गये, उन्होंने 9125 जनसभाएं कीं, 1377 रोड शो किये तथा 9077 नुक्कड़ सभाएं कीं।

जहां विपक्षी दल भाजपा को टक्कर देने के लिये, उनके प्रत्याशी के सामने विपक्ष का एक ही प्रत्याशी खड़ा करने की योजना के साथ, विपक्षी मोर्चा बनाने में समय लगा रहे हैं तथा इस सिलसिले में उनकी पहली मीटिंग 12 जून को पटना में होना संभावित हैं, वहीं भाजपा पूरे दृढ़निश्चय के साथ ऐसी रणनीति बनाने में लगी हुई है कि विपक्षी नेताओं को परस्पर उचित समझबूझ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यह सोच कर्नाटक में भाजपा की भारी हार के बाद, पार्टी को काफी आकर्षक लग रहा है।
- संसद का चुनाव समय से पहले कराने के पक्ष में एक बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि, विपक्ष को एक होने का पूरा मौका नहीं मिल पायेगा।
- दूसरा तर्क है, विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस का ध्यान बंट जायेगा। वो विधानसभा चुनाव पर या संसद के चुनाव पर पूरा ध्यान नहीं दे पायेगी।
- दो चुनाव एक साथ होने से विपक्ष, (मुख्यतया कांग्रेस) के पास धन व साधनों की भारी कमी रहेगी।
- अंतिम तर्क यह है कि, राहुल गांधी अपनी पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आरंभ नहीं कर पायेंगे।
- ऐसा माना जाता है कि, प्रथम चरण में कांग्रेस को कर्नाटक में अच्छा लाभ मिला था।

'महिला चिकित्सक को पी.जी. के अगले सत्र में प्रवेश दिया जाए'

जयपुर, 29 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्र में काम कर चुकी चिकित्सक को बोनस अंकों का लाभ नहीं देने के मामले में आदेश दिए हैं कि, चिकित्सक को पीजी पाठ्यक्रम के अगले सत्र में प्रवेश दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि, इस दौरान किसी दूसरे अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त नहीं किया जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने डॉ. स्नेहा तिवाड़ी की ओर से दायर अपील पर ये आदेश दिए।

- राजस्थान हाई कोर्ट ने डॉ. स्नेहा तिवाड़ी की याचिका पर यह आदेश दिए और कहा कि, अपीलार्थी को बिना किसी गल्ती के पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, अपीलार्थी को बिना किसी गलती पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित किया गया है। हालांकि वर्तमान सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि निकल चुकी है और अपीलार्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

12 जून को पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक की तैयारी जोरों पर

पिछले कुछ माह में नीतीश कुमार ने तो ज्ञान हासिल कर लिया है कि, भाजपा व कांग्रेस से बराबरी की दूरी रखने का चिंतन क्षेत्रीय दलों के लिये सही नहीं है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 जून को पटना में बुलाई जा रही विपक्षी नेताओं की विशाल मीटिंग की तैयारियां की जा रही हैं। जनता दल (यू) सूत्रों ने कहा कि यह मीटिंग इस प्रकार की महत्वपूर्ण मीटिंगों, जो देश के विभिन्न स्थानों पर सम्पन्न होंगी, की शृंखला की पहली मीटिंग होगी।

कर्नाटक में भाजपा की पराजय के बाद, विपक्षी नेताओं के चाल-ठाल और हाव-भाव में इस बात को लेकर नया उत्साह और जोश आ गया है और निरन्तर बढ़ता जा रहा है कि 2024 के संसदीय चुनावों में भाजपा से लड़ने के लिये गैर-भाजपा दल परस्पर सहयोग कर सकते हैं। नये संसद भवन के उद्घाटन का 19 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था। इससे पूर्व, विपक्ष शासित राज्यों के छः मुख्यमंत्री पिछले शनिवार को नीति आयोग की उस मीटिंग में शामिल नहीं हुये थे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

पिछले महीनों में, विपक्षी नेताओं को साथ लाने में, खासतौर से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव तथा अरविन्द केजरीवाल जैसे क्षेत्रीय नेताओं को एक साथ लाने का मामले में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ सफलता मिली है। इससे पूर्व, इन तीनों क्षेत्रीय नेताओं ने कांग्रेस के साथ आने की संभावना को ही खारिज कर दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ममता बनर्जी, अखिलेश यादव व केजरीवाल जैसे नेता भी अब नीतीश के वन-टू-वन उम्मीदवार के फॉर्मूले को स्वीकार करने लगे हैं।
- अतः पटना में विपक्ष के 18 नेता, शरद पवार, नवीन पटनायक, राहुल गांधी व अखिलेश यादव भी विपक्ष के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे।
- एक बिहार के नेता ने, पर, यह भी कटाक्ष किया कि, इन सभी नेताओं को भाजपा सरकार द्वारा प्रेरित ई.डी./सी.बी.आई. के छापों का भय सदा सताता रहता है, अतः उनके एक मंच पर आने का यह भी बड़ा कारण है।

पेपर लीक के आरोपी शेर सिंह मीणा को प्रमोशन

बीकानेर, 29 मई (कासं)। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा को प्रमोट करने के मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया है।

- सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक के आरोपी शेर सिंह मीणा को प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन देने वाले माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को राज्य सरकार ने ए.पी.ओ. कर दिया है।

गौरव को फिलहाल जयपुर में ही हाजरी देनी होगी। पेपर लीक के मास्टरमाइंड अनिल मीणा को वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पद पर प्रमोट किया गया है, इस खबर के बाद राज्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न संसद की पुरानी बिल्डिंग रही न वैसे सांसद और न वैसे दिन, जब ''जर्नलिस्ट'' स्वतंत्र घूमते थे खबर की तलाश में

अंजन रॉय उस जमाने के पुराने वरिष्ठ पत्रकार, पुरानी यादों से घिरे हुए, उदास हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मई। उद्घाटन का दिन आया और चला भी गया। नई संसद का उद्घाटन हो गया, हालांकि बहुतों ने बहिष्कार किया। इसका अर्थ है कि पुरानी संसद का पटाक्षेप हो गया है। अब इसका क्या होगा यह तय नहीं है। हालांकि कुछ का सुझान है कि अब पुरानी इमारतों की तरह इसे भी हैरिटेज होटल बना दिया जाए। वहीं कुछ का सुझाव है कि इसे संसदीय कार्यों से संबंधित मीटिंग व कॉन्फ्रैंस के लिए रखा जाए।

लेकिन सबसे खूबसूरत सुझाव एक जाने माने आर्किटैक्ट की तरफ से आया है कि इसे पूरी गरिमा से पुरातन होने दिया जाए और इसकी मरम्मत नहीं की जाए। प्रकृति को इसका अधिग्रहण करने दिया जाए, इस खूबसूरत इमारत कक्षों में घास-पात, पेड़-पौधे उगने दिए जाएं।

एक पुराने संसदीय संवाददाता एवं पत्रकार के रूप में मेरी इस इमारत से काफी यादें जुड़ी हुई है। चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा, संसदीय संवाददाता व पत्रकार भी इस भवन का प्रमुख हिस्सा रहे है। हम अक्सर यहां बैठा करते थे।

ईमानदारी से कहें तो हम लोग संसद के निर्वाचित सदस्यों के लिए हमेशा परेशानी का सबब रहे हैं। पर हमें न केवल उन्होंने हमेशा बर्दाश्त किया बल्कि प्रोत्साहन भी दिया। कई नेता तो हमारे साथ अक्सर बैठते थे और हमें ऐसे संकेत देते थे कि वे मीडिया में क्या देखना पसंद करते हैं।

यहां अक्सर खुला भाई-भतीजावाद होता था। कुछ पत्रकार कुछ बड़े नेताओं के प्रिय हुआ करते थे तो वे नेता उन्हें अपने चैम्बर में बुलाते थे। यह सर्वज्ञात था, किसी को भी इससे शिकायत नहीं थी। खबरों के लिए खुली प्रतिस्पर्द्धा होती थी पर कोई किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करता था।

- आज के ''डिजिटल युग'' में संसद को ''कवर'' करने वाले जर्नलिस्ट लगभग ''अनुपयोगी'' मान लिये गये हैं, पर, क्या यह प्रजातंत्र के लिये शुभ है?

जब संसद चल रही होती थी। संसद के गलियारे में अक्सर एल.के. अडवानी को अपने प्रिय बी.बी.सी. संवाददाता लम्बे कद के और सैंडल पहनने वाले मार्क टली से बात करते देखा जा सकता था। भाकपा नेता गुरदास दासगुप्ता को वामपंथी रुझान वाले पत्रकारों के साथ देखा जा सकता था। दास गुप्ता के पास बैंकिंग व फाइनैंस के लिए हमेशा नई टिप्स होती थीं।

विशेष तवज्जो देने की इस प्रवृत्ति को अलग रख दें तो संसद के गलियारों में घूमने वाले, खम्बों के इर्द-गिर्द खड़े रहने वाले सभी में भाईचारा था। गौरतलब है कि ये स्तम्भ संसद भवन की पहचान थे। इन दीर्घाओं में जब सभी लोग एकत्र होते थे और बातचीत करते थे, गप्पे मारते थे, तब वहां चाय-काफी वाले भी घूमते दिख जाते थे। और कई बार तो आम हंसी मजाक में बड़े नेता भी शामिल हो जाते थे।

दीर्घा से सटे कक्षों के सामने दोनों सदनों की टेबल्स पर वितरित किए जाने वाले दस्तावेज रखे रहते थे। यह डिजिटल युग से पहले का दौर था जब खबर या कोई भी जानकारी कागजों पर ही दी जाती थी। कई बार लाइन में लग कर इंतजार करने में भी बहुत ऊब और खीज होती थी पर आज तो लाइन में लग कर इंतजार करने की अब और खीज भी याद आ रही है।

हम सुनते हैं कि पत्रकारों को नए संसद भवन से दूर रखा गया है, कुछ को ही बुलाया गया है। वैसे डिजिटल युग में उपस्थित होने के कोई मायने नहीं है। दूसरे पत्रकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां सैंट्रल हॉल, गलियारे, दीर्घा नहीं है जहां पत्रकार ही नहीं नेता भी खुलकर बतियाते थे।

इस साहसिक कदम से खबरें और मुख्य जानकारियां ''लीक होने का दौर खत्म हो जाएगा, जिससे पत्रकार कई बड़ी-बड़ी खोज करने से वंचित हो जाएंगे। अब सूचना बेहद गोपनीय रखी जाएगी। हो सकता है इससे प्रशासन व सत्तारूढ़ पक्ष को लाभ हो लेकिन खबरों वे सूचना के लिए प्रतिस्पर्द्धा लोकतंत्र का कामकाज सुनिश्चित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दरगाह में तोड़फोड़ करने वाले छह गिरफ्तार

उदयपुर, 29 मई (कासं)। गींगला थाना पुलिस ने दरगाह में तोड़फोड करने के मामले में छह जनों को गिरफ्तार किया है।

प्रकरण के अनुसार, गत 23 मई को आदिल पुत्र अशफाक मन्सुरी निवासी सलूम्बर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि, माकडसिमा गांव में पाल के पास स्थित दरगाह में 22 मई रात में अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़फोड की। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ.प्रियंका, पुलिस उप अधीक्षक सुधा पालावत के

- घटना उदयपुर के माकड़सीमा गांव की है, जहां 22 मई की रात पाल के पास की दरगाह पर अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़-फोड़ की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)